पोलियो पर विजय अभी दूर है

एक ज़माना था जब पोलियो एक बड़े संकट के रूप में दुनिया के सामने खड़ा था मगर आज इस संकट से काफी हद तक निजात पा ली गई है। अगर हम मुड़कर आज से 25 साल पहले देखें तो करीब 3 लाख 50 हज़ार लोग हर साल पोलियो की चपेट में आते थे मगर इस साल अब तक दुनिया भर से केवल 60 मामले ही दर्ज किए गए हैं और ये भी महज़ 4 देशों से ही आए हैं।

दुनिया के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पोलियो की आक्रामकता का एहसास था और वे एक दूसरे का ध्यान इस चिंता की ओर खींच रहे थे। मानवता के ऊपर लगे इस कलंक को वे कुछ ही सालों में मिटा देना चाहते थे बिलकुल अपने पूर्ववर्तियों की तरह जिन्होंने अपने प्रयासों से 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया था।

बच्चों को होने वाली एक वायरस जनित बीमारी पोलियोमेलाइटिस को दूर करने के उद्देश्य से 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 9 अरब डॉलर का था। इसके परिणाम स्वरूप पोलियो का प्रसार कम हुआ और इससे प्रभावित बहुत ही कम देश बचे।

खुद को शाबाशी देना और प्रसन्न होना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। अगले दो सालों के लिए यह कार्यक्रम बजट में 1 अरब डॉलर की कमी से जूझ रहा है जो शायद इसकी सफलताओं पर पानी फेर देगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम को 2000 में सम्पन्न होना था फिर यह सीमा 2005 तक पहुंच गई और शायद 2012 भी बीत जाएगा।

यदि तेज़ी से चल रहा टीकाकरण कार्यक्रम किसी कारणवश रुक जाता है तो ऐसी हालत में वायरस के और भी अधिक ताकत से पलटवार की संभावना रहती है। इसके चलते ही नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में पोलियो के प्रसार को नहीं रोका जा सका। इसका असर उनके पड़ोसी देशों पर भी होता है। उदाहरण के लिए, चीन ने वर्ष 2000 में ही खुद को पोलियो-मुक्त घोषित कर दिया था मगर वह अपने उत्तर-पश्चिमी इलाके ज़िनजियांग प्रांत में फिर से इस समस्या से जूझ रहा है जो संभवतः पड़ोसी पाकिस्तान से आई है। डब्लू.एच.ओ. के सह महानिदेशक और उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमुख ब्रूस आइलवर्ड चेताते हैं कि शायद वह दिन बहुत दूर है जब हम यह कह सकेंगे कि पोलियो चंद देशों में एक कभी-कभार होने वाली बीमारी भर है।

इस खतरे को पूरी तरह मिटाने के लिए दुनिया के अमीर देशों को मंदी के बावजूद पोलियो उन्मूलन के लिए आर्थिक सहयोग जारी रखना होगा। साथ ही उन देशों को भी आगे आना होगा जिन्होंने अब तक कोई योगदान नहीं दिया है। पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में जन स्वास्थ्य की इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गंभीर चुनौतियां हैं। ये देश पोलियो वायरस से अपनी खातिर नहीं दुनिया की खातिर लड़ रहे हैं।

पश्चिमी देश, तेज़ी से विकसित हो रहे देश और तेल सम्पन्न सऊदी अरब जैसे सारे देश पोलियो को खत्म करने के लिए और मदद कर सकते हैं। रोटरी इंटरनेशनल, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं को भी मदद जारी रखनी होगी।

अगर दाता अपने पैसे के सही उपयोग का प्रमाण देखना चाहते हैं तो उन्हें एक बार भारत की ओर देखना होगा। 102 करोड़ की आबादी वाले इस देश में वर्ष 2011 में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसके बावजूद भारत की सफलता की तुलना नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से नहीं की जा सकती क्योंकि हर देश की अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं जो टीकाकरण को प्रभावित करती हैं। जैसे इन देशों में धार्मिक

मान्यताएं टीकाकरण विरोधी हैं तो घरेलू आतंकवाद और सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार भी बड़े अवरोधक हैं।

हाल में जेनेवा में घोषित किए गए पोलियो उन्मूलन आकस्मिक एक्शन प्लान में इस बीमारी से जूझने के स्थानीय स्तर के उपायों पर ज़ोर दिया गया है। यदि मौजूदा प्लान नाकाम रहता है तो अधिकारियों को लचीला रुख अपनाना होगा। खास तौर से नाइजीरिया में जो सबसे अधिक संक्रमण से जूझ रहा है और पोलियो के तीनों किस्म के वायरस वहां मौजूद हैं।

उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी मुंह से पिलाए जाने वाले ओरल टीके के साथ ही इंजेक्शन के उपयोग पर विचार कर रहे हैं। इंजेक्शन की मदद से उन लोगों को सहायता मिल सकती जो लगातार ओरल टीका नहीं ले सके हैं। इस तरह से धीरे-धीरे ओरल टीके की जगह इंजेक्शन को अपनाया जा सकेगा। ओरल टीके की एक दिक्कत यह है कि इसका निर्माण जीवित वायरस से किया जाता है और इसका एक साइड इफेक्ट यह होता है कि वायरस फिर से संक्रामक रूप ले सकता है।

पोलियो उन्मूलन से इतर और आगे सोचना आकर्षक लग सकता है। जैसे खसरा उन्मूलन पर विचार चल रहा है मगर इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा न हो कि एक और उन्मूलन कार्यक्रम के चक्कर में हम सामान्य टीकाकरण को भुला दें।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक अलग ही प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव है कि 2020 तक सामान्य टीकाकरण का लक्ष्य 90 प्रतिशत हासिल किया जाए और जिन बीमारियों की रोकथाम टीकों से हो सकती है, उनके कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जाए। अगर ये उद्देश्य हासिल कर लिए जाते हैं शायद उतनी वाहवाही न मिले जितनी पोलियो उन्मूलन के चलते मिलेगी मगर ये लक्ष्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***